

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़  
आर.ए.एस.

निगरानी संख्या-33/2021

1. हिदायत आयु 66 साल पुत्र करीम खां जाति कायमखनी निवासी सिगड़ी, पंचायत समिति मण्डावा, तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू।

-निगरानीकार

-बनाम-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू।
2. असगर खां पुत्र हासम खां जाति कायमखानी निवासी सिगड़ी तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनू।

- गैर निगरानीकार

निगरानी अंधारा 97 राज0 पंचायती राज अधि01994 बखिलाफ विनश्चय  
या आदेश दिनांक 01.9.2021 विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डावा।

उपस्थिति:-

1. श्री विनोद कुमार गिल , एडवोकेट -----निगरानीकार की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी एडवोकेट-----गैर निगरानीकार नं0 1 की ओर से।
3. श्री राजेश कुमार मीणा, एडवोकेट-----गैर निगरानीकार नं02 की ओर से।

-निर्णय-

दिनांक 29.8.2022

उक्त निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 1.9.2021 विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डावा के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि- निगरानीकार ने ग्राम सीगड़ी में अपने पट्टाशुदा भूमि में रिहायस बना रखी है उक्त भूमि आबादी भूमि है। निगरानीकार की एक बिना आधार के शिकायत असगर खां पुत्र हासम खां द्वारा श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डावा को की गई जिसमें आक्षेप लगाया गया कि उसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया। उक्त बिना क्षेत्राधिकार की शिकायत के विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डावा ने निगरानीकार नंबर 1 को नोटिस जारी कर दिया। गैर निगरानीकार नंबर 1 को अतिक्रमण बाबत नोटिस देने का क्षेत्राधिकार नहीं है। उक्त नोटिस देने से पहले ना तो कोई जांच करवाई तथा ना ही किसी पंचायत की स्थाई समिति या उप समिति का कोई संकल्प पारित किया गया जिसके बिना विकास अधिकारी नोटिस जारी नहीं कर सकता। निगरानीकार के विरुद्ध क्षेत्राधिकार के बार जाकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
झुंझुनू



कार्यवाही कर रहा है। निगरानीकार अपने पट्टाशुदा आवासीय भूमि में आबाद है गैर निगरानीकार नंबर 2 जहां आबाद है उसके घर के आगे सीमेन्टेड सड़क बनी हुई है, इसलिए गैर निगरानीकार नंबर 2 ने गलत आक्षेप लगाया है कि उसके घर जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। गैर निगरानीकार नंबर 2 को रास्ते बाबत कोई समस्या है तो उसको ग्राम पंचायत के पास जाना चाहिए था या सिविल न्यायालय में जाना चाहिये था। गैर निगरानीकार नंबर 1 ने बिना क्षेत्राधिकार के नियम विरुद्ध व बिना किसी संकल्प या बिना किसी स्थाई समिति या उप समिति के संकल्प नोटिस जारी किया जो काबिले निरस्त है। अतः निगरानी पेशकर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार कर निगरानीकार के विरुद्ध जारी विनश्चय/आदेश दिनांक 01.9.2021 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में सीधे तौर पर विकास अधिकारी को नोटिस देकर कार्यवाही करने या सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। निगरानीकार को जारी नोटिस विधिविरुद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकार को जारी नोटिस को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार नंबर 2 की ओर से निवेदन किया गया कि- वर्ष 1983 में ग्राम पंचायत सीगड़ा के सरपंच जयकरण सिंह ने ग्राम सीगड़ी में आवासीय कालोनी के लिए लोगों को बसने के लिए जगह नहीं थी एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित इन्दिरा गांधी हरिजन बस्तियों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्कीम निकालकर बजट पारित किया गया था और ग्राम पंचायतों में इन्दिरा आवास हरिजन बस्तियों का मकान बनाकर निर्माण कर निःशुल्क आवंटित किये गये थे। तत्कालीन सरपंच जयकरण सिंह द्वारा जिला कलक्टर के आदेश से ग्राम पंचायत सीगड़ा के लिए भूमि आवंटित कराई थी। उसी आवंटन से साईट प्लान बनाकर कोलोनी के रूप में निर्माण कर लोगों को अलग-अलग आवंटन किया गया था। जिला कलक्टर द्वारा आवंटित भूमि में से बची हुई भूमि में जिनको आवासीय मकान की आवश्यकता थी और जो जरूरतमंद थे उसमें सामान्य लोगों को भी आवंटन किया गया था। उसी भूमि में असगर खान को प्लॉट नंबर 9 व 10 आवंटित किये गये थे। हिदायत खां द्वारा अतिक्रमण कर रास्ते में बाधा डाल रखी है। जिस रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है वह मौके पर 20 फुट का रास्ता आवागमन के लिए खुला है। भंवरलाल जो सिगड़ी का निवासी नहीं है, फर्जी तरीके से खंगाराम का पुत्र बना हुआ है उसने अतिक्रमण कर रखा है। जबकि उसको उसके

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
झुन्झुनू

नाम से कोई प्लॉट आवंटित नहीं है। हिदायत खां अतिक्रमी है। कानून उसको किसी प्रकार की कानूनी रिलिफ नहीं दी जा सकती। अतिक्रमी को कभी भी बेदखल किया जा सकता है। अतिक्रमी हिदायत खां ने राज्य सरकार से आवंटित पानी की टंकी सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। रास्ते पर विधायक कोटे से सीमेन्टेड रोड के लिए राज्य सरकार से प्राप्त बजट से ठेकेदार द्वारा पत्थर, डबोरे डालकर निर्माण कार्य चालू करना चाहा तो हिदायत खां एण्ड पार्टी ने निर्माण कार्य नहीं करने दिया। उससे व्यथित होकर असगर खां द्वारा ग्राम पंचायत को रिपोर्ट की लेकिन ग्राम पंचायत सरपंच असगर खान से राजनैतिक द्वेषता के कारण सरपंच ने यह कह दिया कि हमारे पास रिकार्ड नहीं है। हम कार्यवाही नहीं कर सकते। फिर असगर खां द्वारा पुलिस थाना मण्डावा में रिपोर्ट की तो थानाधिकारी ने मौका देखकर रास्ता खुलवाने की चेष्टा की, लेकिन राजनैतिक दबाव के कारण उन्होंने यह कहकर इन्कार कर दिया कि पंचायत का मामला है वो करेगी। इस संबंध में थानाधिकारी ने जांच भी की थी और जयकरण सिंह सरपंच व अन्य लोगों के कथन भी लेखबद्ध किये गये थे। इसके बाद तहसील में रिपोर्ट की, हल्का पटवारी व गिरदावर ने भी अतिक्रमण माना। फिर पंचायत समिति झुंझुनू के विकास अधिकारी ने जांच की और मामला सही पाया गया और उनके द्वारा बेदखली की कार्यवाही पूर्ण होने से पूर्व ही झूठे आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो विधिक प्रावधानों के विपरित है। निगरानीकार अतिक्रमी है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त अतिक्रमी के पास कोई फर्जी पट्टा है जिसको हाजा न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है, आदि। अंत में अतिक्रमी हिदायत खां व स्व बृजलाल के पुत्रान जिस पर भंवरलाल अतिक्रमी है उसको बेदखल करने का आदेश पारित किया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में विवादित रास्ते की भूमि ग्राम पंचायत सीगड़ा की आबादी भूमि होना दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है। गैर निगरानीकार का कथन है कि उसके आने-जाने के रास्ते को निगरानीकार ने अवैध रूप से अतिक्रमण करके रोक दिया है और जिसकी शिकायत उसके द्वारा ग्राम पंचायत सीगड़ा, उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू तहसीलदार, थानाधिकारी मण्डावा, विकास अधिकारी आदि को की गई, लेकिन अतिक्रमण हटाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत समिति मण्डावा की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अवैध अतिक्रमण को लेकर गैर निगरानीकार ने कई जगह शिकायत की है। उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू द्वारा भी विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डावा को प्रकरण की जांच करवाकर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। विकास अधिकारी पंचायत मण्डावा द्वारा जांच समित का गठन किया जाकर प्रकरण की जांच करवायी गई है। जांच समिति ने बाद जांच निगरानीकार सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण करना बताया है जिस पर विकास अधिकारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
झुंझुनू

पंचायत समिति द्वारा अतिक्रमियों को नोटिस जारी किये गये हैं। गैर निगरानीकार का कथन है कि राजनैतिक कारणों से ग्राम पंचायत कार्यवाही नहीं कर रही है, ऐसी स्थिति में अवैध अतिक्रमण की जांच करना और अतिक्रमियों को नोटिस जारी करना विधिसम्मत प्रतीत होता है। निगरानीकार को चाहिए था कि पहले वे विकास अधिकारी, पंचायत समिति मण्डावा के समक्ष उपस्थित होकर नोटिस के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करते उसके उपरांत विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डावा के बाद सुनवाई अंतिम आदेश से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में हाजा न्यायालय में निगरानी करना उचित प्रतीत होता। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी खारिज की जाती है। निगरानीकार नोटिस के संबंध में अपना जवाब विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डावा को प्रस्तुत करे। विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डावा को निर्देशित किया जाता कि प्रकरण में दोनों पक्षों को सुना जाकर अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो बेदखली की कार्यवाही हेतु प्रकरण ग्राम पंचायत सीगड़ा को भिजवाया जावे। आदेश की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डावा को भिजवायी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ़्तर हो।



( जगदीश प्रसाद )  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 29.8.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( जगदीश प्रसाद )  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
झुंझुनू